भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2965
दिनांक 12 दिसंबर, 2024

पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य

2965. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पेट्रोलियम उत्पादों का उनकी खपत की तुलना में कुल कितना उत्पादन होता है;
(ख) आयातित पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा और उनका मूल्य कितना है तथा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किन-किन देशों से किया जा रहा है;
(ग) देश के उपभोक्ताओं को खरीद मूल्य की तुलना में अधिक मूल्य पर डीजल और पेट्रोल उपलब्ध कराए जाने के क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं को राहत देने पर विचार कर रही है;
(ड.) क्या सरकार देश के किसानों को सस्ती कीमतों पर डीजल उपलब्ध कराने के लिए राजसहायता देने पर विचार कर रही है;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (छ): वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, देश में पेट्रोलियम उत्पादों का कुल उत्पादन और खपत क्रमशः 276 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) और 234 एमएमटी थी। एलपीजी, ईंधन तेल और पेटकोक आदि जैसे कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए देश ने विभिन्न भौगोलिक स्थलों जैसे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आदि में स्थित देशों से 22933 मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत वाले 49 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य के साथ उत्पादन, खपत और आयात का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	2023-24 (पी)
उत्पादन (एमएमटी)	276
खपत (एमएमटी)	234
आयात की मात्रा (एमएमटी में)	49
निर्यात की मात्रा (एमएमटी में)	63
आयात का मूल्य (मिलियन यूएसडी में)	22933

स्रोतः पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ पीःअनंतिम एमएमटीः मिलियन मीट्रिक टन

पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित होते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं।

भारत अपनी क्रूड ऑयल की जरूरतों का 85% से अधिक आयात करता है। क्रूड ऑयल के मूल्य (भारतीय बास्केट) $55/बीबीएल (मार्च 2015) से बढ़कर $113/बीबीएल (मार्च 2022) हो गई हैं और अत्यधिक अस्थिर बनी हुई हैं।

सरकार और पीएसयू ओएमसीज द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में दो बार नवंबर, 2021 और मई, 2022 में क्रमशः 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी है, जो उपभोक्ताओं को पूर्णतः प्रदान की गई थी, जिसके परिणाम स्वरुप घरेलू तौर पर, पेट्रोल और डीजल के मूल्य घटकर क्रमशः 94.77 रुपए/लीटर और 87.67 रुपए/लीटर हो गए हैं। कतिपय राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत पहुँचाने के लिए राज्य वैट दरों को कम कर दिया था। मार्च, 2024 में ओएमसीज ने भी, पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्यों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की थी।

भारत सरकार ने आम नागरिको को उच्च अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों से सुरक्षित रखने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं, जिनमें कच्चे तेल की आयात बास्केट में विविधता लाना, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाना आदि शामिल है।

हाल ही में पीएसयू ओएमसीज ने अंतर-राज्य भाड़े का युक्तिकरण किया है। इससे राज्यों के भीतर सुदूर भागों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के रुप में पेट्रोलियम ऑयल और ल्यूब्रिकेंट (पोओएल) डिपो से दूर, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। इस पहल ने राज्य में पेट्रोल या डीजल के अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के बीच के अंतर को भी कम कर दिया है।

****